27-06- 2019 - EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAMME-2019 at NSI

मिल में देरी से गन्ना पहुंचने पर किसान व चीनी को घाटा

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

कानपुर | वरिष्ठ संवाददाता

गन्ना खेतों से मिल तक पहुंचने में होने वाली देरी से सिर्फ मिल मालिकों को नहीं, बल्कि किसानों को भी नुकसान होता है। जितनी देरी से गन्ना मिल पहुंचता है, उसका वजन उतना कम हो जाता है। साथ ही चीनी का उत्पादन भी कम होता है ऐसे में किसान को कम लागत मिलती है तो चीनी का उत्पादन भी कम होता है।

यह बात चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुशील सोलोमन ने कही। कहा, सूचना तकनीक का उपयोग कर गन्ने की कटाई और मिलों में पेराई के समय अंतराल को कम करना है।

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने अतिथि सम्मानित किए।

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में तीन दिवसीय एग्जक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन बुधवार को आईआईटी रूड़की के प्रो. विनय शर्मा, डॉ. सुशील सोलोमन और संस्थान के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने किया। डॉ. सोलोमन ने कहा कि स्मार्ट शुगरकेन की प्रजातियां विकसित करने की जरूरत है। प्रो. विनय शर्मा ने चीनी मिलों व आसवनियों (डिस्टलरी) में तकनीक व गैर-तकनीक कर्मचारियों की संरचना को बदलने पर जोर दिया।

इथेनॉल प्लांट लगाने पर जोर

पुणे से आए डॉ. एमएस सुंदरम ने बड़ी संख्या में इथेनॉल प्लांट लगाने पर जोर दिया। कहा, इससे न सिर्फ मिल मालिकों को अधिक लाभ होगा बल्कि पेट्रोल में मिलाकर इसका फायदा पूरे देश को होगा। प्रो. नरेंद्र मोहन ने नीतियों की जानकारी दी। कहा, पेराई सत्र 2019-20 लगभग 14.6 मिलियन टन चीनी के भंडारण के साथ चालू होने की संभावना है। यह हमारी लगभग छह माह की घरेलू खपत से अधिक है। उन्होंने कहा कि चीनी के स्थान पर बी शीरे व रस से अधिक इथेनॉल के उत्पादन की आवश्यकता है। ब्राजील, आस्ट्रेलिया और थाईलैंड में गन्ने का मूल्य 24 डॉलर प्रति टन है जबकि देश में यह लगभग 42 डॉलर प्रति टन है। इस मौके पर प्रो. डी स्वेन, एके गर्ग आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से यूपी के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा, गुजरात और नेपाल में स्थित चीनी मिलों व डिस्टलरी में कार्यरत अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बी शीरे व रस से अधिक इथेनॉल के उत्पादन की जरूरत : प्रो. मोहन

कानपुर (एसएनबी)। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक प्रो. नरेन्द्र मोहन ने कहा कि आगामी सत्र में चीनी के अधिक उत्पादन को देखते हुए चीनी के स्थान पर बी शीरे एवं रस से अधिक इथेनॉल के उत्पादन की आवश्यकता है। यह विशेष रूप से इथेनाल की मांग और उत्पादन के अर्थशास्त्र को देखते हुए अत्यन्त आवश्यक है।

प्रो. मोहन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान सभागार में आयोजित एक्जीक्यूटिव डेवलपमेन्ट प्रोग्राम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पेराई सत्र 2017-18 तथा 2018-19 में चीनी मिलों ने अतिरिक्त (सरप्लस) चीनी का उत्पादन किया था और आगामी पेराई सत्र 2019-20 में भी चीनी का उत्पादन खपत से अधिक होगा। आगामी पेराई सत्र में करीब 14.6 मिलियन टन चीनी के भंडारण के साथ चालू होने की संभावना है, जो हमारी करीब छह माह की घरेलू खपत से अधिक है। उन्होंने कहा कि भारत में अन्य अग्रणी चीनी उत्पादक देशों की तुलना में गन्ने का मूल्य अधिक है, फलतः इससे चीनी के निर्माण की लागत और बढ़ जाती है और अन्तरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना संभव नहीं होता है। प्रो. मोहन ने कहा कि एक ओर ब्राजील, आस्ट्रेलिया तथा थाईलैण्ड में गन्ने के मूल्य 24-24 डॉलर प्रति टन के बीच हैं, वहीं दूसरी तरहफ हमारे देश में यह करीब 42 डॉलर प्रति टन है। उन्होंने गन्ने के मूल्य निर्धारण के लिए सरकार द्वारा गठित डॉ. रंगराजन समिति की सिफारिशों के बारे में जिसके तहत किसानों व चीनी मिल मालिकों के बीच प्राप्त हुए लाभ को एक पूर्व निर्धारित अनुपात में बांटने का सुझाव दिया है उसे अथवा कोई अन्य तार्किक नियम फार्मूला निश्चित करने

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में एक्जीक्यूटिव डेवलपमेन्ट प्रोग्राम

करने पर जोर दिया।

इस मौके पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की के प्रो. विनय शर्मा, चन्द्रशेखर आजाद कृषि विवि के कुलपति डॉ. सुशील सोलोमन, जेपी मुखर्जी एण्ड एसोसिएट पूणे के डॉ. एमएस सुन्दरम, ग्लोबल केनशुगर सर्विसेज नयी दिल्ली के डॉ. जीएससी राव, प्रो. डी स्वेन, एके गर्ग आदि वक्ताओं ने विचार व्यक्त किये।

राष्ट्रीय सहारा
क्लासीफाइड विज्ञापन
सूचना
सूचना

बंपर पैदावार देगा स्मार्ट गन्ना, रोगमुक्त भी होगा

जागरण संवाददाता, कानपुर : आने वाले समय में किसानों के खेतों में स्मार्ट गन्ने की खेती होगी। यह ऐसा गन्ना होगा जिसमें अधिक पैदावार, उच्च शर्करा, बॉयोमास व रोग प्रतिरोधक क्षमता सहित कई गुण होंगे। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआइ) व गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ समेत देश के कई संस्थानों में एक साथ इतनी विशेषताओं वाले गन्ने की प्रजाति विकसित करने पर अनुसंधान चल रहा है। संस्थान के खेतों में इसका सफल परीक्षण किया गया। यह जानकारी एनएसआइ में बुधवार को हुए एक्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के दौरान चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुशील सोलोमन ने दी।

स्मार्ट गन्ना इस प्रकार का होगा जिसकी सिंचाई कम पानी में की जा सकेगी। जलवायु परिवर्तन के कारण सर्दी व गर्मी की समयावधि कम व अधिक होने का असर भी इस पर नहीं पड़ेगा। वर्तमान में गन्ने की औसत पैदावार 72 से 80 टन प्रति हेक्टेयर की जा रही है। स्मार्ट गन्ने की उपज सौ से 120 टन प्रति हेक्टेयर होगी। इस गन्ने की खूबी यह भी होगी कि एक प्रजाति का इस्तेमाल कई वर्षों तक किया जा सकेगा। वर्तमान में जिन प्रजातियों की पैदावार की जा रही है वह सात से आठ वर्ष में आउट डेटेड हो जाती हैं। यह ऐसा गन्ना होगा जिसे कटाई के बाद तीन से पांच दिन तक खुले में रखे जाने पर भी यह सूखेगा नहीं। कार्यक्रम में एनएसआइ निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने बताया कि अभी देश में गन्ने की औसत पैदावार 4110 लाख टन है जबकि स्मार्ट गन्ना इससे कहीं अधिक उपज देगा। इस दौरान आइआइटी रुड़की के प्रो. विनय शर्मा ने कहा कि गन्ना मिल के अधिकारियों को कर्मचारियों के लिए नजीर बनना चाहिए। जेपीएमए पुणे के एमडी डॉ. एमएस सुंदरम ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को महत्वपूर्ण बताया।

उन्नत उत्पादन

- 2020 तक सौ से 120 टन प्रति हेक्टेयर हो जाएगी गन्ने की पैदावार
- एनएसआइ व गन्ना संस्थान में मल्टी क्वालिटी गन्ने पर हो रहा अनुसंधान

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में बोलते सीएसए कुलपति प्रो. सुशील सोलोमन • जागरण

'Sugar in surplus, nation needs to produce ethanol'

TIMES NEWS NETWORK

Kanpur: A three-day executive development programme organised by National Sugar Institute concluded here on Wednesday.

The programme was attended by the top executives of sugar factories and distilleries from UP, Maharashtra, Karnataka, Bihar, Haryana, Gujarat and Nepal. Prof. Vinay Sharma from IIT-Roorkee discussed about proper structuring of sugar factories and distilleries with respect to manpower so as to harness the potential of available resources to maximum possible extent. He stressed on defining role and responsibilities of each worker with higher officials taking lead and inspiring the subordinates to achieve pre-set goals.

Vice-chancellor, CSA University of Agriculture and Technology, Sushil Solomon, presented model of raw material management system so as to avoid post harvest losses. "As sugarcane is a perishable crop, any delay in its crushing reduces both its weight and the sugar content.

Since price to the farmers is paid on the basis of its weight, delay in its crushing is neither in the interest of farmer or miller", he said. Introduction of information technology on a larger scale to keep a track of age of crop, its harvesting and actual supply is need of the hour, he added.

Director, National Sugar Institute, Prof Narendra Mohan in his address presented details of policy interventions made during the last couple of year by the Government of India for its sustainability.

"We are surplus in sugar from the past two sugar seasons, and next year (2019-20) also, we are going to be surplus in sugar. The next sugar season is likely to open with a carryover of about 14.6 million tons of sugar which is more than six months of our domestic consumption", Prof Mohan said. There is dire need to produce more ethanol than sugar in view the economics of ethanol production and its demand, he added.

"Our cane cost is the highest among the major sugar producing country, which makes our sugar costlier and uncompetitive in the international market. While the sugarcane price in Brazil, Australia and Thailand is USD24-27 per ton, it is about US$ 42 per ton in India, he further said.

He suggested fixation of sugarcane price on the basis of sharing of revenues between farmers and millers in predetermined ratio as suggested by Dr Rangarajan Committee or through some logical formula.

मुनाफे के लिए स्मार्ट शुगरकेन प्रजातियां बोएं गन्ना किसान

कानपुर। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (एनएसआई) में विभिन्न प्रांतों तथा नेपाल के चीनी मिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के कार्यक्रम में सुझाव दिया गया कि गन्ना किसान अधिक मुनाफा कमाने के लिए गन्ने की 'स्मार्ट शुगरकेन' प्रजातियां बोएं। सीएसए के कुलपति डॉ. सुशील सोलोमन ने कहा कि गन्ने की ऐसी नई प्रजातियां विकसित की जाएं जो कम पानी और कम लागत में अधिक पैदावार दे सकें। गन्ने की कटाई और पेराई में अधिक गैप न हो। एनएसआई के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा, गुजरात की चीनी मिलों के कार्यकारी अधिकारियों ने शिरकत की। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने कहा कि दो सालों में देश का चीनी उद्योग लाभ की स्थिति में आ रहा है। प्रोफेसर डी. स्वेन ने चीनी मिलों के संचालन और रखरखाव में प्रतिदिन आने वाली समस्याओं और उनके हल के बारे में बताया। ब्यूरो